

मुख्य समाचार :-

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सात दशमलव आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है।
- उत्तराखण्ड के दुर्गम, दूरस्थ और सर्दियों में हिमाच्छादित रहने वाले तीन शहरों और 131 गांवों में जनगणना आज से शुरू।
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देशभर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 22 हस्तियों को सम्मानित किया।
- और... उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में समूह-ग के 553 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया।

प्रधानमंत्री सोशल मीडिया संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सात दशमलव आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया।

जनगणना

हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड के दुर्गम, दूरस्थ और सर्दियों में हिमाच्छादित रहने वाले तीन शहरों और 131 गांवों में जनगणना आज से शुरू हो गई है। लगभग 52 हजार की जनसंख्या की गणना का कार्य 30 सितंबर तक चलेगा।

आज से सितंबर से 30 सितंबर तक प्रदेश के चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ के 131 गांवों के साथ ही तीन शहरी निकाय क्षेत्रों केदारनाथ, बदरीनाथ एवं गंगोत्री में जनगणना की जाएगी। इस अवधि में इन क्षेत्रों में घर-घर जाकर जनसंख्या की गिनती होगी। इसके बाद एक से पांच अक्टूबर तक संशोधन चरण (रिविजनल राउंड) चलेगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद देहरादून जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन ने अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर नगर निगम देहरादून के सभी सौ वार्डों में प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी अनुपालन व नियमित निगरानी के लिए 50 सेक्टर अधिकारी नामित किए गए हैं।

अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा ने बताया कि अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक का निर्माण करने वाले उद्योगों और फैक्ट्रियों पर भी विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सेक्टर अधिकारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम देहरादून के सभी वार्डों में नियमित निगरानी के लिए नगर निगम स्तर से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी।

सम्मान

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देशभर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 22 हस्तियों को सम्मानित किया। इसमें 15 को भारत गौरव सम्मान और चार को भारत युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भानु प्रकाश रेड्डी, टीटीडी सदस्य, आंध्र प्रदेश सरकार और पूर्व प्रधान वन संरक्षक समीर सिन्हा और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के चेयरमैन तेजेंद्र पाल त्यागी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।

इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि सम्मान उपलब्धियों की स्वीकृति के साथ भविष्य में और बेहतर करने की जिम्मेदारी भी है। सफलता के पीछे अनुशासन, निरंतर परिश्रम और चुनौतियों के बीच लक्ष्य पर टिके रहने का संकल्प महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि प्रतिभाशाली, जिम्मेदार और चरित्रवान नागरिकों से होगा। देश की प्रतिभाओं को अपनी क्षमता और उपलब्धियों को समाज और राष्ट्र की प्रगति से जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देना होगा।

स्मूह ग विज्ञप्ति

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने विभिन्न विभागों में समूह-ग के तहत कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर सहायक, निबंधन लिपिक, टेलीफोन ऑपरेटर और सर्वे लेखपाल समेत कुल 553 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www-sssc-uk-gov-in ij जाकर आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए आठ सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू

होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि सात अक्तूबर है। इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन की अवधि 12 से 14 अक्तूबर है। लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 15 नवंबर तय गई है। अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना है। लिपिकीय पदों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4 हजार की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है। आयु की गणना 01 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। सामान्य पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है। 100 अंकों की दो घंटे की वस्तुनिष्ठ ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी।

सड़कें बंद

प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लोक निर्माण विभाग ने बारिश से बंद सड़कों की सूची जारी है। विभाग के अनुसार प्रदेश में करीब

143 सड़कें बंद हैं। इनमें 107 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई की हैं, जबकि शेष सड़कें लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमों प्रभावित सड़कों को खोलने में जुटी हैं। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सड़कों को खोलने के लिए टीमों लगातार मौके पर काम कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 सितंबर के बाद मानसून के हल्का पड़ने के साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों के डामरीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैदानी इलाकों में जहां मौसम अनुकूल हो रहा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का डामरीकरण किया जा रहा है।

विमान सेवा

पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून रूट पर आज सप्ताह में छह दिन विमान सेवा शुरू कर दी गई है। छह दिन विमान का संचालन होने से बड़ी संख्या में यात्री आसान और सुगम सफर कर सकेंगे।

नैनीसैनी से सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को दिल्ली और देहरादून के लिए 42 सीटर विमान सेवा संचालित है। अब आज से इन रूटों पर विमान सप्ताह में सिर्फ रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिन उड़ान भरेगा। एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के लिए यह सेवा सप्ताह में छह और देहरादून के लिए पांच दिन संचालित होने के साथ ही बुकिंग प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। इससे पर्यटकों को भी काफी सुविधा मिलेगी और सीमांत क्षेत्र के पर्यटन को भी नई उड़ान मिलने की उम्मीद है।

नाबालिग लापता बच्चे

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने लापता बालिकाओं और नाबालिग बच्चों को पता लगाने के लिए विशेष टीम कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिवालय में पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन स्माइल का नवीनतम डाटा उपलब्ध करवाने के साथ ही मानव एवं बाल तस्करी के मामलों का केस-वाइज विश्लेषण किया जाए। मुख्य सचिव ने तस्करी के नेटवर्क व संगठित मामलों की पहचान कर उनकी रोकथाम के लिए प्रभावी एवं मजबूत तंत्र विकसित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग के मामलों में मैदानी क्षेत्रों सहित पर्वतीय क्षेत्रों में भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के पोर्टल का शीघ्र एकीकरण किया जाए।